

डॉलर-रुपया स्वैप

प्रलिमिंस के लिये:

डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी, तरलता प्रबंधन पहल, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट, सीमांत स्थायी सुवधि, स्थायी जमा सुवधि, मौद्रिक नीति।

मेन्स के लिये:

मौद्रिक नीति।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रज़िर्व बैंक** (RBI) ने अपनी तरलता प्रबंधन पहल के हिस्से के रूप में 5 बिलियन डॉलर-रुपए की स्वैप नीलामी आयोजित की। इस कदम से डॉलर का प्रवाह मज़बूत होगा और वित्तीय प्रणाली से रुपए की नक़ासी होगी।

- इससे महँगाई कम होगी और रुपए में मजबूती आएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग आधारित मुद्रास्फीति में नमिनलखिति में से कसिके कारण/वृद्धि हो सकती है? (2021)

- इक्स्पैन्सनरी पालिसी
- राजकोषीय प्रोत्साहन
- मज़दूरी का मुद्रास्फीति-सूचकांक
- उच्च क्रय शक्ति
- बढ़ती ब्याज दरें

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1, 2 और 4
- केवल 3, 4 और 5
- केवल 1, 2, 3 और 5
- 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

डॉलर-रुपया स्वैप नीलामी:

- यह एक वदेशी मुद्रा उपकरण (Forex Tool) है जिससे केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का उपयोग दूसरी मुद्रा या इसके वपिरीत खरीद के लिये करता है।
- डॉलर-रुपया खरीद / बिक्री स्वैप:** केंद्रीय बैंक भारतीय रुपए (INR) के बदले बैंकों से डॉलर (अमेरिकी डॉलर या USD) खरीदता है और तुरंत बाद की तारीख में डॉलर बेचने का वादा करने वाले बैंकों के साथ एक वपिरीत (रुपए को बकना) सौदा करता है।
- जब केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री की जाती है तो समान मात्रा में रुपए की नक़ासी होती है, इस प्रकार ससिस्टम में रुपए की तरलता को कम होती है।
 - इन स्वैप परचालनों (Swap Operations) में कोई वनिमिय दर या अन्य बाज़ार जोखमि नहीं होते हैं क्योंकि लिन-देन की शर्तें अग्रमि रूप से नरिधारित की जाती हैं।

RBI की योजना:

- RBI ने बैंकों को 5.135 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेचे और साथ ही स्वैप नपिटान अवधि के अंत में डॉलर को वापस खरीदने के लिये सहमति प्रदान की है।

- यहाँ आशय यह है कि केंद्रीय बैंक वकिरेता से डॉलर प्राप्त करता है तथा दो वर्ष की अवधि के लिये संभव न्यूनतम प्रीमियम वसूल करता है।
- तदनुसार नीलामी की नचिली सीमा पर बोली लगाने वाले बैंक नीलामी में सफल होते हैं।
 - डॉलर की दर 75 रुपए मानकर ससि्टम की तरलता 37,500 करोड़ रुपए कम हो जाएगी।

वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या नमिनलखिति में से कसिकी अनुपलब्धता से संबंधित है? (2015)

- वस्तुओं और सेवाओं
- सोना और चांदी
- डॉलर और अन्य कठोर मुद्राएँ
- नरियात योग्य अधशेष

उत्तर: (c)

आरबीआई अब इसका सहारा क्यों ले रहा है?

- ससि्टम में अधशेष तरलता 7.5 लाख करोड़ रुपए आँकी गई है, जसि मुद्रासफीत को संतुलित रखने के लिये रोकने की ज़रूरत है।
- आमतौर पर केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ाने या नकद आरकषति अनुपात (CRR) बढ़ाने जैसे पारंपरिक साधनों का सहारा लेता है लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 - यह नकारात्मक प्रभाव मौद्रिक नीति के अधूरे रूप में देखा जा सकता है।
 - इसलिये आरबीआई द्वारा पछिले वर्ष एक अलग टूलकटि- वेरिबल रेट रविर्स रेपो ऑकशन (Variable Rate Reverse Repo Auction-VRRR) का इस्तेमाल कया गया।
- हालाँकि हाल ही में VRRR नीलामयिों को बैंकों द्वारा कम कर दिया था, क्योंकि नकदी बाज़ार ने तत्काल और बेहतर प्रतफिल की पेशकश की जसिसे RBI को वदिशी मुद्रा नीलामी जैसे दीर्घकालिक तरलता समायोजन उपकरण पर वचिर करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

स्वैप का प्रभाव:

- तरलता को कम करना: प्रमुख रूप से तरलता प्रभावित होगी जो वर्तमान में औसतन लगभग 7.6 लाख करोड़ रुपए घटेगी।
- भारतीय रुपए के मूल्यहरास की जाँच: बाज़ार में डॉलर के प्रवाह से रुपए को मजबूती मिलेगी जो पहले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 के स्तर पर पहुँच चुका है।
- मुद्रासफीत पर नयित्रण: जब मुद्रासफीत में वृद्धि का खतरा होता है तो आरबीआई आमतौर पर ससि्टम में तरलता को कम कर देता है। नमिनलखिति कारकों के कारण मुद्रासफीत बिढना तय है:
 - तेल की कीमतों में वृद्धि: रूस-यूकरेन युद्ध के मद्देनज़र कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आने वाले दनिों में मुद्रासफीत बिढना तय है।
 - संस्थागत नविश का बहरिवाह: वदिशी पोर्टफोलियो नविशक भारत से धन नकाल रहे हैं। उन्होंने मार्च 2022 में अब तक भारतीय शेयरों से 34,000 करोड़ रुपए नकाल लिये हैं, जसिका रुपए पर गंभीर दबाव पड़ा है।

चलनधि प्रबंधन पहल क्या है?

- केंद्रीय बैंक की 'तरलता प्रबंधन' पहल को कुछ वशिषिट फ्रेमवर्क, उपकरणों के समूह और वशिष रूप से उन नयिमों के रूप में परभाषित कया जाता है, जसि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक रज़िर्व की मात्रा को नयित्त्रति कर कीमतों (यानी अल्पकालिक ब्याज दरों) को नयित्त्रति करने हेतु कया जाता है, जसिका अल्पकालिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनशिचति करना होता है।
 - बैंक रज़िर्व का आशय उस न्यूनतम राशि से है, जो वत्तितीय संस्थानों के पास होनी अनविर्य है।
- 'तरलता प्रबंधन' पहल रज़िर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग कया जाने वाला एक उपकरण है, जो बैंकों को पुनरखरीद समझौतों (रेपो) के माध्यम से ऋण लेने या बैंकों को रविर्स रेपो समझौतों के माध्यम से रज़िर्व बैंक को ऋण देने की अनुमति देता है।
 - इस फ्रेमवर्क के तहत वभिनिन उपकरण हैं:
 - रेपो/रविर्स रेपो नीलामी
 - सीमांत स्थायी सुवधि (MSF)
 - वदिशी मुद्रा स्वैप

वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: यदि भारतीय रज़िर्व बैंक एक वसितारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का नरिणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

- वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
- सीमांत स्थायी सुवधि दर में बढ़ोतरी
- बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

खान और खनजि अधिनियम, 1957 में संशोधन

प्रलिस के लिये:

खान और खनजि अधिनियम 1957, भारत में कोयला।

मेन्स के लिये:

संशोधन का महत्त्व, MMDR अधिनियम।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धातुओं के पोटाश, पन्ना और प्लैटिनम समूह सहित कुछ खनजिों की रॉयल्टी दरों को नरिदषिट करने के लिये [खान और खनजि \(विकास और वनियिम\) अधिनियम](#) की दूसरी अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- **MMDR अधिनियम, 1957** भारत में खनन क्षेत्र को नरिदषिट करता है, साथ ही खनन कार्यों के लिये खनन पट्टे प्राप्त करने एवं देने की आवश्यकता को नरिदषिट करता है।

भूमिका:

- देश की खनजि संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के लिये नीलामी के माध्यम से खनजि रियायतें देने की नई व्यवस्था की शुरुआत करने हेतु वर्ष **2015 में अधिनियम** में संशोधन किया गया था।
- खनजि क्षेत्र को गति देने के लिये वर्ष 2021 में अधिनियम में संशोधन किया गया। सुधारों के तहत सरकार ने खनजि ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि, देश में व्यापार करने में आसानी तथा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** में खनजि उत्पादन के योगदान को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।
 - सुधारों में सांख्यिकी आवश्यकताओं, कैप्टिव खानों से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाने, कैप्टिव और गैर-कैप्टिव खानों के बीच वभिजन, खनजि-रियायतों की नीलामी एवं हस्तांतरण, राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), राष्ट्रीय खनजि सूचकांक (NMI), नजि क्षेत्र को शामिल करना आदि से संबंधित प्रावधान हैं।
- खान मंत्रालय ने खनजिों की खोज का कार्य बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए हैं, जिससे नीलामी हेतु अधिक ब्लॉक की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
 - न केवल लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे पारंपरिक खनजिों के लिये बल्कि पृथ्वी के अंदर स्थित खनजिों, उर्वरक खनजिों, संवेदनशील खनजिों के आयात के लिये भी अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि हुई है।
 - पछिले 4-5 वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनजि अन्वेषण निगम लिमिटेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य किया और राज्यों को रिपोर्ट सौंपी है।

वर्गित वर्षों के प्रश्न

नमिनलखित खनजिों पर वचिर कीजिये: (2020)

1. बेंटोनाइट
2. क्रोमाइट
3. कायनाइट
4. सल्लिमैनाइट

उपर्युक्त में से कौन-सा/से खनजि आधिकारिक तौर पर भारत में नामित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

खनजि रियायत:

- तीन प्रकार की खनजि रियायतें हैं, जैसे- टोही परमिट (RP), पूर्वकृषण लाइसेंस (PL) और खनन पट्टा (ML)।
- RP कषेत्रीय, हवाई, भूभौतिकीय या भू-रासायनिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से एक खनजि के प्रारंभिक पूर्वकृषण के लिये प्रदान किया जाता है।
- PL खनजि जमा की खोज, पता लगाने या साबति करने के उद्देश्य से संचालन के लिये दिया जाता है।
- ML किसी भी खनजि के संचालन हेतु दिया जाता है।

वर्षों के प्रश्न

भारत के खनजि संसाधनों के संदर्भ में नमिनलखिति युग्मों पर वचिर कीजयि: (2010)

खनजि 90% प्राकृतिक स्रोत

1. ताँबा - झारखंड
2. नकिलि - ओडिशि
3. टंगस्टन - केरल

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्वीकृत से संबंधति प्रमुख बटु:

- अनुमोदन से ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटनिम ग्रुप ऑफ़ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलबिडेनम के संबंध में खनजि ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चिति होगी जिससे मूल्यवान वदिशी मुद्रा भंडार की बचत करने वाले इन खनजिों के आयात में कमी आएगी।
 - ग्लूकोनाइट और पोटाश का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। धातुओं के प्लेटनिम समूह और अंडालूसाइट और मोलबिडेनम उद्योगों में उपयोग किये जाने वाले उच्च मूल्य वाले खनजि हैं।
- खान मंत्रालय ने खदानों की नीलामी में बेहतर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये रॉयल्टी की उचित दरों का प्रस्ताव किया है।
 - रॉयल्टी एक ऐसा शुल्क है जो स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारों द्वारा किसी खदान में उत्पादति खनजिों की मात्रा या खदान से बेचे गए खनजिों से प्राप्त राजस्व या लाभ पर लगाया जाता है।
- खान मंत्रालय इन खनजि ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम करने के लिये आवश्यक खनजिों के औसत बिक्री मूल्य (ASP) की गणना हेतु एक पद्धति प्रदान करेगा।
- अंडालूसाइट, सिलीमैनाइट और कायनाइट, जो कर्पोलीमॉर्फ खनजि हैं, के लिये रॉयल्टी की दर समान स्तर पर रखी जाती है।
 - कर्पोलीमॉर्फ एक ही रासायनिक संरचना वाले ऐसे खनजि होते हैं, जिनकी क्रिस्टल संरचनाएँ अलग होती हैं।
- इस अनुमोदन से खनन कषेत्र के साथ-साथ वनिरिमाण कषेत्र में सशक्तीकरण के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जो समाज के एक बड़े वर्ग के समावेशी विकास को सुनिश्चिति करने में मदद करेगा।
 - इस मंजूरी से देश में पहली बार ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटनिम ग्रुप ऑफ़ मेटल्स, अंडालूसाइट और मोलबिडेनम के खनजि ब्लॉकों की नीलामी सुनिश्चिति होगी।

वर्षों के प्रश्न:

भारत में ज़िला खनजि फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

1. खनजि समृद्ध ज़िलों में खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना
2. खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना
3. राज्य सरकारों को खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

भारत में खनजिों का नियमन:

■ खनजिों का स्वामित्व:

- राज्य की सीमा के भीतर स्थिति खनजिों का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है।
 - 'ज़िला खनजि फाउंडेशन' भारत में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से स्थापित वैधानिक निकाय हैं। वे खान एवं खनजि (विकास व वनियमन) अधिनियम, 1957 से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं।
 - 'ज़िला खनजि फाउंडेशन' का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और कर्षेत्रों के हितों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना है।
- प्रादेशिक जल या भारत के अनन्य आर्थिक कर्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनजिों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है।
 - 'इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी' (ISA) वह संगठन है, जिसके माध्यम से UNCLOS के सदस्य समग्र मानव जाति के लाभ हेतु कर्षेत्र में सभी खनजि-संसाधन-संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं नियंत्रण करते हैं।

■ खनजि रियायतें प्रदान करना:

- राज्य सरकारें खान एवं खनजि (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनजि रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा के भीतर स्थिति सभी खनजिों के लिये खनजि रियायतें प्रदान करती हैं।
- हालाँकि खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में नरिदषिट खनजिों के लिये केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनुसूची I में कोयला और लग्निनाइट जैसे खनजि तथा यूरेनियम और थोरियम युक्त "दुर्लभ मृदा" समूह के खनजि शामिल हैं।
- इसके अलावा केंद्र सरकार समय-समय पर कुछ खनजिों को 'लघु' खनजिों के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके लिये आवेदन प्राप्त करने और अनुदान देने की प्रक्रियाओं पर नरिणय लेने की पूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास हैं।
- रियायतें, रॉयल्टी की दरें तय करना, नरिधारित करिया और आदेशों को संशोधित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है।
 - लघु खनजिों के उदाहरणों में भवन नरिमाण में प्रयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मट्टि व रेत शामिल हैं।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये:

1. वैश्विक महासागर आयोग अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल की खोज एवं खनन हेतु लाइसेंस प्रदान करता है।
2. भारत को अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल में खनजि अन्वेषण हेतु लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
3. 'दुर्लभ मृदा तत्त्व' अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्र तल पर मौजूद हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

स्रोत: पी.आई.बी.

तापी-पार-नर्मदा लकि परियोजना

प्रलमिस के लयि:

तापी-पार-नर्मदा लकि परियोजना, केन-बेतवा ।

मेन्स के लयि:

नदयिों को जोड़ने का कार्यक्रम और संबधति चुनौतयिों, जल संसाधन ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में कुछ आदवासयिों ने पार-तापी-नर्मदा नदी लकि परियोजना के खलिाफ वरिोध तेज़ कर दयिा है, जसिका उल्लेख वतित मंत्री के बजट भाषण (2022-23) में कयिा गया था ।



पृष्ठभूमि:

- इन परियोजनाओं को वर्ष 2010 में मंजूरी दी गई थी, जब केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच त्रपिकीय समझौते पर हस्ताक्षर कयिे गए थे ।
- वतित मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा किराज्यों के बीच सहमतकिे बाद पाँच नदी जोड़ो परियोजनाएँ शुरु की जाएंगी ।
 - ये परियोजनाएँ हैं- दमनगंगा-पजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी ।
 - केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की सरकार की परियोजना राष्ट्रीय परपिरेकष्य योजना के तहत पहली परियोजना है ।
 - नेशनल रविर लकिगि प्रोजेक्ट (NRLP) जसिँ औपचारकिे रूप से राष्ट्रीय परपिरेकष्य योजना के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य देश की 'जल अधशिष' वाली नदी घाटयिों (जहाँ बाढ़ की स्थतिरिहती है) से जल की 'कमी' वाली नदी घाटयिों (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थतिरिहती है) को जोड़ना है ताकि अधशिष कषेत्रों से अतरिकित जल को कम जल वाले कषेत्रों में स्थानांतरति कयिा जा सके ।

पार-तापी-नर्मदा नदी लकि परियोजना:

- पार-तापी-नर्मदा लकि परियोजना पश्चिमी घाट के जल अधशिष कषेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ (गुजरात) के पानी की कमी वाले कषेत्रों में पानी स्थानांतरति करने का प्रस्ताव करती है ।
- इस लकि परियोजना में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में प्रस्तावति सात जलाशय शामिल हैं ।
- सात प्रस्तावति जलाशयों का जल 395 कमी. लंबी नहर के माध्यम से संचालति सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा पर) से छोटे रास्ते के कषेत्रों की सचिाई करते हुए लयिा जाएगा ।
 - योजना में प्रस्तावति सात बाँध झेरी, मोहनकवचली, पाइखेड़, चसमांडवा, चकिकर, डाबदार और केलवान हैं ।

- इससे सरदार सरोवर का पानी बचेगा जिसका उपयोग सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सिंचाई के लिये किया जाएगा।
- इस लिके में मुख्य रूप से सात बाँधों तीन डायवर्ज़न वयिर, दो सुरंगों, 395 कमी. लंबी नहर, 6 बजिली घरों और कई क्रॉस-ड्रेनेज कार्यों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

परियोजना के लाभ:

- सिंचाई लाभ प्रदान करने के अलावा यह परियोजना चार बाँध स्थलों पर स्थापित बजिलीघरों के माध्यम से 93.00 MkWh जलवियुत उत्पन्न करेगी।
- जलाशयों से नचिले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से राहत भी मिलेगी।

नर्मदा नदी के बारे में:

- नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में वधिय श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है।
- इसके अपवाह क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में तथा इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में है।
- जबलपुर (मध्य प्रदेश) के निकट यह नदी 'धुँआधार प्रपात' का निर्माण करती है।
- नर्मदा नदी के मुहाने में कई द्वीप हैं जिनमें से अलियाबेट सबसे बड़ा है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: हरिन, ओरसंग, बरना तथा कोलार आदि।
- इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थिति में प्रमुख जल-वियुत परियोजनाएँ हैं।

तापी/ताप्ती नदी:

- पश्चिम की ओर बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है।
- यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है।
- इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

पार नदी:

- यह गुजरात में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम नासकि, महाराष्ट्र के वडपाड़ा गाँव के पास होता है।
- यह अरब सागर में गिरती है।

वर्षों के प्रश्न:

हाल ही में नमिनलखिति में से कनि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया गया है? (2016)

- कावेरी और तुंगभद्रा
- गोदावरी और कृष्णा
- महानदी और सोन
- नर्मदा और ताप्ती

उत्तर: (b)

नदी जोड़ो परियोजना (ILR):

- **उद्देश्य:**
 - देश की 'जल अधशेष' वाली नदी घाटियों (जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है) से जल की 'कमी' वाली नदी घाटियों (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति रहती है) को जोड़ना है ताकि अधशेष क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।
- **आवश्यकता:**
 - **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना:** भारत मानसून की वर्षा पर निर्भर है जो अनियमित होने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन भी है। नदियों को आपस में जोड़ने से अतिरिक्त वर्षा और समुद्र में नदी के जल प्रवाह की मात्रा में कमी आएगी।
 - **कृषि सिंचाई:** इंटरलकिंग द्वारा अतिरिक्त जल को न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके न्यून वर्षा आधारित भारतीय कृषि क्षेत्रों में सिंचाई संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
 - **जल संकट को कम करना:** यह सूखे और बाढ़ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है।
 - **अन्य लाभ:** इससे जलवियुत उत्पादन, वर्ष भर नेविगेशन, रोज़गार सृजन, सूखे जंगलों और भूमि के रूप में पारस्थितिकि लाभ की भरपाई होगी।
- **चुनौतियाँ:**

- **पर्यावरणीय लागत:** परियोजना से नदियों की प्राकृतिक पारस्थितिकी में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है।
- **जलवायु परिवर्तन:** इंटरलकिंग सिस्टम में जल अधशेष बेसिन (जहाँ जल की मात्रा अधिक है) से जल की कमी वाले 'बेसिन' में जल का हस्तांतरण किया जाता है।
 - यदि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी भी प्रणाली की मूल स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी अवधारणा नरिर्थक हो जाती है।
- **आर्थिक लागत:** अनुमान है कि नदियों को आपस में जोड़ने से **सरकार पर व्यापक वित्तीय बोझ** पड़ेगा।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15000 कर्मी. तक फैले नहरों के नेटवर्क से लगभग 5.5 मिलियन लोग वसिथापति होंगे, इनमें ज्यादातर आदिवासी और किसान वर्ग प्रभावित होंगे।

आगे की राह

- भारत को पानी की एक-एक बूँद को संरक्षित करने, अपव्यय को कम करने, संसाधनों के समान वितरण के साथ ही भूजल को बढ़ाने की ज़रूरत है।
- **स्थानीय समाधान (जैसे बेहतर संचाई पद्धति) और वाटरशेड प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- सरकार को वैकल्पिक रूप से **राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना (NWP)** पर विचार करना चाहिये, जो नदी के पानी के बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच संघर्ष को समाप्त कर सकता है, क्योंकि यह सरिफ अतिरिक्त बाढ़ के पानी का उपयोग करता है जो बिना दोहन के समुद्र में चला जाता है।

वर्षों प्रश्न

नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्यों? (2013)

1. यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है।
2. यह वधिय और सतपुड़ा के बीच बहती है।
3. भूमिका ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

फसलों की ई-खरीद

प्रलिमिंस के लिये:

मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), ई-नाम पोर्टल, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACF)

मेन्स के लिये:

कृषि विपणन, कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा ई-खरीद' पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहाँ **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर 14 फसलों की खरीद की जाती है।

- इन फसलों में गेहूँ, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूँग, मूँगफली, अरहर, उड़द और तिल शामिल हैं।

- यह पोर्टल खेती में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के साधन के रूप में डिजिटल शासन (ई-शासन) को तेज़ी से अपनाने की दृष्टि में महत्वपूर्ण कदम है।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद असीमति है।
2. अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहाँ बाज़ार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

पोर्टल से संबंधित मुख्य बिंदु:

- पोर्टल को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र शुरू किया गया था।
- दो वर्ष से भी कम समय में राज्य के कुल किसानों में से 8.71 लाख या 80% से अधिक ने रबी सीज़न में पोर्टल पर पंजीकरण कराया।
- पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन बिक्री की सुविधा प्रदान करना है, जिसके तहत राज्य की 81 मंडियों को 'ई-नाम' (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) पोर्टल से जोड़ा गया है।
 - 'ई-नाम' प्लेटफॉर्म एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल प्रदान करता है, जो कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा APMC (कृषि उपज बाज़ार कमोडिटीज़) मंडियों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।

फसलों की खरीद:

- **उद्देश्य:** खाद्यान्न खरीद की सरकार की नीतिका व्यापक उद्देश्य किसानों के लिये MSP सुनिश्चित करना और कमज़ोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
 - यह प्रभावी बाज़ार हस्तक्षेप को भी सुनिश्चित करता है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखने के साथ ही देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।
 - मूल्य समर्थन के तहत खरीद मुख्य रूप से किसानों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु की जाती है जो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
- **नोडल एजेंसी:** भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है जो अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूँ और धान की खरीद करती है।
 - भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दृष्टि-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय पूल के लिये राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा मोटे अनाज की खरीद की जाती है।
- **CACP की भूमिका:** प्रत्येक रबी/खरीफ की फसल के मौसम के दौरान फसल से पहले, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सफारिश के आधार पर खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है।
- **राज्य सरकारों की भूमिका:** खाद्यान्नों की खरीद की सुविधा के लिये FCI और विभिन्न राज्य एजेंसियों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों में बड़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किये हैं।

वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से कारक/नीतियाँ हाल के दिनों में भारत में चावल की कीमत को प्रभावित कर रही है? (2020)

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य
2. सरकार द्वारा व्यापार
3. सरकार द्वारा भंडारण
4. उपभोक्ता सब्सिडी

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4

- (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

ई-मंडी किसानों की मदद कैसे करेगी?

- **बिचौलियों का एकाधिकार:** मौजूदा बुनियादी ढाँचे के साथ कृषि उपज केवल निकटतम कृषि बाजार तक पहुँचती है जो कृषि उपज बाजार (कृषि उपज बाजार वस्तु) के अधिकार क्षेत्र में है।
 - यात्रा, पैकगि और उपज की छँटाई का खर्च उठाने के बाद किसान स्थानीय मंडियों में पहुँचते हैं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बेचने की प्रतीक्षा करते हैं।
 - किसानों को छँटाई, ग्रेडिंग और अन्य आवश्यक कृषि प्रक्रियाओं के लिये स्थानीय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस प्रकार उन बिचौलियों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं जो हमेशा भरोसेमंद या ईमानदार नहीं होते हैं।
- **किसानों के हितों के लिये हानिकारक:** यह अघोषित एकाधिकार जो अस्तित्व में है, वस्तु की वृद्धि और कृषि मूल्य शृंखला के मुक्त प्रवाह को प्रभावित रहा है, यह स्थानीय किसानों तथा उनकी आजीविका के लिये भी हानिकारक है।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं? (2017)

1. यह कृषि वस्तुओं के लिये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
2. यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुँच प्रदान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रौद्योगिकी कृषि की मदद कर कैसे सकती है?

- **आधुनिक प्रौद्योगिकी की तैनाती:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बलॉकचेन, मशीन लर्निंग, क्लाउड-स्मार्ट एडवाइज़री, जियो-टैगिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए आधुनिक तकनीक व डिजिटल मशीनरी की शुरुआत के साथ पछिले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में नविशकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।
 - हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के खेतों में कीटनाशकों का छड़िकाव करने के लिये भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
- **किसानों को लाभ:** डिजिटल मंडियों किसानों को थोक व्यापारियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बना रही हैं, इस प्रक्रिया में शामिल बिचौलियों को समाप्त कर रही हैं, जो उनके आंदोलन और फसल के प्रकार, कस्मि और मूल्य बढि को चुनने की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) अनुमोदित किया जाता है- (2015)

- (a) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा
(b) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा
(c) वपिणन और नरीक्षण नदिशालय, मंत्रालय द्वारा
(d) कृषि उपज मंडी समिति द्वारा

उत्तर: (a)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को फरि से शुरू करेंगे

प्रलमिस के लयि:

अंतरमि व्वापार समझौता, मुक्त व्वापार समझौता ।

मेन्स के लयि:

भारत-कनाडा मुक्त व्वापार समझौते का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और कनाडा ने व्वापार और नविश पर पाँचवीं मंत्रसितरीय वार्ता (MDTI) आयोजति की, जहाँ मंत्रयिों ने भारत-कनाडा **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते** (CEPA) हेतु वार्ता को औपचारकि रूप से फरि से शुरू करने पर सहमत व्वाक्य की और एक अंतरमि समझौते या प्रारंभकि प्रगतशील व्वापार समझौते पर भी वचिार कयिा ।

- इससे पूर्व भारत और ऑस्ट्रेलया ने घोषणा की थी कविे मार्च 2022 में एक अंतरमि व्वापार समझौता और उसके 12-18 माह बाद एक **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता** (CECA) करने को तैयार हैं ।



प्रमुख बदि

- अंतरमि समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, उत्पत्तकि के नयिमों, स्वच्छता और फाइटोसैनटिरी उपायों, व्वापार हेतु तकनीकी बाधाओं और वविाद नपिटान में उच्च सतरीय प्रतबिद्धताएँ शामिल होंगी तथा पारस्परकि रूप से सहमत कसिी भी अन्य क्षेत्रों को भी शामिल कयिा जा सकता है ।
- दोनों पक्षों ने फारमास्यूटकिल्स और महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ पृथ्वी खनजिों के साथ-साथ पर्यटन, शहरी बुनयािदी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा एवं खनन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ज़ोर दयिा ।
- दोनों देश दालों में कीट जोखमि प्रबंधन के लयि कनाडा द्वारा लागू प्रणाली को मान्यता देने और भारतीय कृषि वस्तुओं जैसे- स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और केला आदि के लयि बाज़ार पहुँच के संबंध में गहन कार्य करने पर सहमत हुए ।
- कनाडा भारतीय जैवकि नरियात उत्पादों की सुवधा के लयि **APEDA (कृषि एवं और प्रसंसकृत खाद्य उत्पाद नरियात वकिस प्राधकिरण)** को 'अनुरूपता सत्यापन नकियाय' (CVB) की मान्यता दयि जाने के अनुरोध की शीघ्र जाँच करने पर भी सहमत हुआ ।
 - CVB एक ऐसा संगठन के रूप में होता है, जसिने कनाडाई खाद्य नरिीक्षण एजेंसी के साथ-साथ कनाडाई खाद्य नरिीक्षण एजेंसी अधनियिम की उप-धारा 14(1) के तहत प्रमाणन नकियायों का आकलन करने, मान्यता के लयि अनुशंसा और नगिरानी करने के लयि एक समझौता कयिा है ।
- मंत्रयिों ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीली आपूर्ता शृंखला स्थापति करने के महत्त्व को स्वीकार कयिा और इस क्षेत्र में सहयोग पर वचिारों का आदान-प्रदान कयिा ।

अंतरमि व्वापार समझौता:

- कसिी मुक्त व्वापार समझौते को अंतमि रूप देने से पहले दो देशों या व्वापारकि बलों के बीच कुछ वस्तुओं के व्वापार पर टैरफि को उदार बनाने हेतु एक

अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement- ITA) अथवा 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' (Early Harvest Trade Agreement) का उपयोग किया जाता है।

- अंतरिम समझौते पर सरकार का जोर रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और विवादास्पद मुद्दों को बाद में हल करने का अवसर हो।
- 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' जो पूर्ण पैमाने पर FTA में नहीं होते हैं, इन्हें अन्य देशों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कविश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं।
- पूरे सौदे पर एक साथ बातचीत करना अक्सर फायदेमंद होता है, क्योंकि 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' एक पक्ष के लिये एफटीए की दिशा में काम करने हेतु प्रोत्साहन को कम कर सकता है।

व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (CEPA):

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
- साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
- CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।
- भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।

कनाडा के साथ भारत के वर्तमान व्यापार संबंध:

- भारत, कनाडा का 11वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाजार (**Export Market**) है और कुल मिलाकर 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है।
 - वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2020-21 में भारत द्वारा कनाडा से 2.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत में कनाडा की वाणिज्यिक प्राथमिकताएँ भारत के नीतित उद्देश्यों और उन क्षेत्रों पर लक्षित हैं जहाँ कनाडा को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इन प्राथमिकताओं में शामिल हैं:
 - पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा के निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वकांक्षाओं का समर्थन करना।
 - वित्तपोषण, उपकरण, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से भारत को इसकी पर्याप्त शहरी एवं परिवहन बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना।
 - कनाडा और भारतीय शैक्षणिक एवं तकनीकी कौशल संस्थानों के बीच अधिक सहयोग के माध्यम से उन्नत शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण।
 - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्यिक अनुसंधान एवं विकास।
 - भारत की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने हेतु खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि।

स्रोत: पी.आई.बी.